PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Wednesday 17th June 2015, Page: 14
Width: 18.23 cms, Height: 11.51 cms, a4, Ref: pmin.2015-06-17.33.114

मोदी सरकार सिफारिश पर नए सिरे से कर रही विचार

डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाएं लिखना हो सकता है अनिवार्य

प्रियंवदा सहाय

नई दिल्ली। आम आदमी के लिए सस्ती दवाओं का रास्ता खोलने के लिए संसद की स्थायी समिति की जिस सिफारिश को यूपीए सरकार ने तवज्जो नहीं दिया था, मोदी सरकार उस पर नए सिरे से विचार कर रही है। डॉक्टरों के जरिए केवल जेनरिक दवाएं लिखने की अनिवार्यता वाली दो साल पुरानी सिफारिश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि देश की बड़ी आबादी तक सस्ती दवाओं की पहुंच हो सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की अध्यक्षता वाली वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने 2013 में लोकसभा में अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी। फार्मा उद्योग में एफडीआई से संबंधित समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गरीबों तक सस्ती दवाओं को पहुंचाने के लिए जेनरिक दवाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर डॉक्टरों के जरिए केवल जेनरिक दवाएं ही लिखी जाती हैं तो इससे 70 फीसदी लोग आसानी से दवा खरीद पाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझाया गया कि कैंसर के इलाज के लिए ब्रांडेड कंपनियों की दवाओं की कीमत जहां करीब दो लाख रुपये है वहीं जेनरिक दवा की कीमत महज आठ हजार रुपये है। इसलिए देश में भारतीय दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को दरकिनार कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। इस संदर्भ में आम जनता की राय, डॉक्टरों और दवा निर्माता कंपनियों से भी जल्द बातचीत शुरू की जाएगी। वहीं शांता कुमार ने बताया कि उन्होंने इस सिफारिश पर गौर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का आश्वासन दिया है। शांता ने कहा कि भारत का स्वदेशी दवा उद्योग दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका, यूरोप व यूनीसेफ तक भारत से जेनरिक दवाओं की खरीद करते हैं लेकिन खुद भारत में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत दो लाख करोड़ रुपये की ब्रांडेड दवाओं का निर्यात करता है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में भारतीय डॉक्टर जेनरिक दवाओं की लिखते नहीं हैं। अगर डॉक्टर केवल जेनरिक दवाओं को लिखें तो भारतीय दवा उद्योग का कारोबार दोगुना हो जाएगा। नड्डा को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अगर सिफारिशों को मान लिया जाए तो एक रुपये अतिरिक्त खर्च किए बगैर गरीबों तक सस्ती दवाओं को पहुंचाया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वह जल्द मुलाकात कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेंगे।

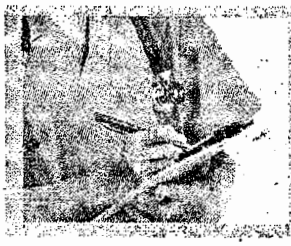

- स्थायी समिति की इस सिफारिश को यूपीए सरकार ने नहीं दी थी तवज्जो
- देश की बड़ी आबादी तक सस्ती दवाएं पहुंचाने को जेनरिक दवाओं का महत्व बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय का जोर